



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 496]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 27, 2014/फाल्गुन 8, 1935

No. 496]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 27, 2014/PHALGUNA 8, 1935

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2014

का.आ. 578(अ).—केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 4 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा उच्च न्यायालय, दिल्ली के न्यायमूर्ति श्री सुरेश कैंत की अध्यक्षता में “विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण” का गठन इस न्याय-निर्णयन करने के प्रयोजन के लिए करती है कि स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इण्डिया (सिमी) को विधिविरुद्ध संगम घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं या नहीं, जो केन्द्र सरकार द्वारा अपनी दिनांक 1 फरवरी, 2014 की अधिसूचना संख्या का.आ. 299(अ), जो दिनांक 1 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित हुई है, के अंतर्गत पहले ही घोषित किया जा चुका है।

[फा. सं. 14017/2/2014-एन.आई.-III]

रश्मि गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2014

S.O. 578(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 read with sub-section (1) of Section 4 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby constitutes the “Unlawful Activities (Prevention) Tribunal”, consisting of Shri Justice Suresh Kait, Judge of the High Court of Delhi, for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the Students Islamic Movement of India (SIMI) as an unlawful association, which has already been declared as such by the Central Government vide its notification number S.O. 299(E), dated the 1st February, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 1st February, 2014.

[F. No. 14017/2/2014-NI-III]

RASHMI GOEL, Jt. Secy.